

प्रभक,

राजेश सिंह,

उप सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,

श्रीनगर गांववाल।

शिक्षा अनुभाग-8 (तकनीकी)

देहरादून: दिनांक 24 मार्च, 2006

विषय:-

जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय पाली0 गौवर के आवासीय भवन हेतु पुनरीक्षित आगमन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2321/नि0प्र0हि0/जिला योजना/2005-06 दिनांक 26.10.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पाली0 गौवर के टाइप-4 के एक आवस एवं टाइप-1 आवस निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-82/प्र0हि0/2003 दिनांक 29.3.2003 द्वारा रु0 10.82 लाख के आगमन पर वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-950/XXIV(8)/2005 दिनांक 9.12.2005 द्वारा अवशेष धनराशि रु0 0.82 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्य के लिए कुल रु0 18.25 लाख के पुनरीक्षित आगमन पर प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, अवशेष धनराशि रु0 18.25 लाख-रु0 10.82 लाख = रु0 7.43 लाख के साक्ष रु0 5.31 लाख (रुपये पांच लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि, संख्या-416/XXIV(8)/2005-56/2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा जिला योजना-पालीटेक्निक का सुरुद्धीकरण-वृहद निर्माण कार्य हेतु आपके निर्देशन पर रखी गयी धनराशि रु0 27.12 लाख में से, प्रदान करते हुए व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2-

आगमन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें खिड़कूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3-

कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगमन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4-

कार्य पर उतनी ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5-

एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6-

उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा शेष बचे पूर्व में जारी उक्त शासनादेश के अनुसार रहेगी।

7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टताओं के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8- कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का माली-मालि निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप कार्य किया जायें।

9- आगमन में जिन मरों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

11- इस संबंध में होने वाला चार्ज विलीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202- शिक्षा खेती पर पूर्णतः परित्याग-02- तकनीकी शिक्षा-104- बट्टित - आयोजनागत-91-जिला योजना-9101-पाली0 का सुदृढीकरण - 24- वृद्ध निर्माण कार्य के नामों जाला जायेगा।

12- यह आदेश विल विभाग अशासकीय संख्या-1229/विल अनुभाग-3/2006 दिनांक 24.3.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(राजेश सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. काषाधिकारी, पी.डी।
3. निदेशक, कोषागार एवं विल सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. विल अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उOPO राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
7. बजट राजकीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
8. जिलाधिकारी यमौली, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आशा है,
(सजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।